भारत संघ

बनाम

राम किशन

7 मई, 1971

[एस.एम. सिकरी, सी.जे., जी.के. मीटर, सी.ए. वायडलिंगम,

पी.गगन मोहन रेड्डी और आई.डी. दुआ, जेजे.]

पंजाब पुलिस नियम, आर। 16, 38 - सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी किसी स्थान पर छापा मारते समय अपराध करना-जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी देने में विफलता-विभागीय जांच की वैधता और पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करना।

प्रतिवादी, एक पुलिस कांस्टेबल, ने एक स्थान पर छापा मारा, और छापे के दौरान उस स्थान पर एक व्यक्ति को चाकू से घायल कर दिया। वह अपनी वर्दी के बिना घटना स्थल पर गया। धारा 324, के तहत एक मामला उनके खिलाफ एल. पी. सी. दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिया गया और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने एक याचिका दायर कीः बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर चुनौती देना कि आर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। 16.38 पंजाब पुलिस के नियमों का पालन नहीं किया गया।

उच्च न्यायालय ने अपील में मुकदमे का फैसला सुनाया।

इस न्यायालय में अपील करते हुए, अभिनिर्धारित किया कि:

वादी एक पुलिस अधिकारी के अधिकार का प्रयोग करने का इरादा रखता था, भले ही वह सादे कपड़ों में हो। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए कार्य जनता के साथ उनके आधिकारिक संबंध के संबंध में एक आपराधिक अपराध थे और विभागीय

कार्यवाही में आरोप में उनका विवरण लापरवाही के रूप में आर के प्रभाव से बचने का प्रयास था। 16.38. उप-आर के तहत (1) नियम के अनुसार अपराध के बारे में तत्काल जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए थी।

वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई जानकारी दिए जाने का कोई सबूत नहीं था, न ही इस बात का कोई सबूत था कि जिला मजिस्ट्रेट ने फैसला किया कि जांच उन पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी जिन्होंने इसे संचालित किया था। चूँकि उप-आर का उल्लंघन हुआ था। (1) नियम के अनुसार बर्खास्तगी का आदेश अवैध था। [759 ई-एच, 760-एच]

दिल्ली प्रशासन बनाम चानन शाह, [1969] 3 एस.सी.आर. 653 ने इसका अनुसरण किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 750/1966।

पंजाब उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच, दिल्ली ने 1962 के सी.आर.एस.ए संख्या 256-D में पारित निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा दिनांकि अपील 4 मार्च, 1964 से।

अपीलार्थी की ओर से सॉलिसिटर-जनरल जगदीश स्वरूप और आर. एन. सचथे।

प्रत्यर्थी की ओर से एन.डी. बाली और डी.डी. शर्मा।

न्यायालय का निर्णय सीकरी, सी. जे. द्वारा सुनाया गया था।

प्रतिवादी, राम किशन, हेड कांस्टेबल, पुलिस अधीक्षक (केंद्रीय) श्री डी.सी. शर्मा द्वारा 3 सितंबर, 1957 को उनके खिलाफ पारित बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाले मुकदमे में विफल रहे। मुख्य हमला दोगुना था। सबसे पहले यह आरोप लगाया गया था कि श्री डी.सी. शर्मा जिला पुलिस अधीक्षक नहीं थे और इसलिए वादी को

बर्खास्त करने के हकदार नहीं थे। दूसरी ओर यह आरोप लगाया गया कि चूंकि पंजाब पुलिस नियमों के नियम 1 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए वादी के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई अवैध थी।

22 तारीख को क्या हुआ, इस बारे में वादी का बयान यही जून, 1957 था। 22 जून, 1957 को वह अपराध की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर थे और अपने चक्कर लगाते समय उन्हें सूचना मिली कि कुछ जुआरी राउस एवेन्यू पर एक सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे थे। नतीजतन, उन्होंने एक रेडिंग पार्टी का आयोजन किया। जुआरी, जो हरिजन थे, पुलिस दल को बाहर निकालते थे और दल के सदस्यों को कुछ चोट पहुँचाते थे। इस डर से कि उन्हें घसीटा जाएगा, उन्होंने निगम के एक हरिजन सदस्य के साथ-साथ संसद के एक हरिजन सदस्य से संपर्क किया, जिन्होंने वादी के अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में फोन किया, इससे पहले कि वादी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए घटना स्थल से पुलिस स्टेशन पहुंचे।

सरकार का संस्करण यह था कि पादरी था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दरियागंज के पास साइकिल चोरी की जांच के लिए प्रतिनियुक्त और उन्हें राउज एवेन्यू, हार्डिंग ब्रिज में तैनात नहीं किया गया था। इस बात से इनकार किया गया कि वादी को राउस एवेन्यू में एक सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के बारे में कोई जानकारी मिली थी। इसके विपरीत सरकार की ओर से यह आरोप लगाया गया कि वादी अन्य सिपाहियों के साथ मोहन लाल, नाथू आदि को फंसाना चाहता था और एक ओर वादी और उसके अन्य सहयोगियों और दूसरी ओर मोहन लाल और अन्य लोगों के बीच हाथापाई हुई।

उप-न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया।

वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने अपील को स्वीकार कर लिया और वादी को यह घोषणा करने के लिए एक डिक्री प्रदान की कि

3 सितंबर, 1957 का आदेश उसे सेवा से गायब करना अवैध और अधिकार से बाहर है। उन्होंने रुपये 1926/10/- वेतन और भत्तों के कारण के लिए एक फरमान भी पारित किया।

सरकार ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। मामला जे. महाजन के सामने आया, जिन्होंने पाया कि पंजाब पुलिस नियमों के नियम 16.38 का उल्लंघन किया गया था, लेकिन क्योंकि यह यूनियन वी. राम किशन (सीकरी, सीजे) था। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस नियम 16.38 निर्देशिका थी और अनिवार्य नहीं थी, उन्होंने मामले को एक खंड पीठ को भेज दिया।

न्यायाधीश मेहर सिंह ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि "बाबू राम उपाध्याय [(1)] (ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 751) के मामले को देखते हुए इस नियम को अनिवार्य माना जाना चाहिए, हालांकि अन्यथा, नियम की भाषा पर ही मेरी राय है कि यह एक अनिवार्य नियम है"। उन्होंने आगे कहा कि "इस मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था और उन्हें पहले उपनियम (1) और फिर उपनियम (2) के तहत निर्णय लेने का कोई अवसर नहीं मिला था।" उन्होंने पहली अपीलीय अदालत से सहमति व्यक्त की कि आरोपों के बयान में आरोप यह एक ऐसी जानकारी थी जो प्रतिवादी द्वारा जनता के साथ अपने आधिकारिक संबंध के संबंध में एक आपराधिक अपराध के आयोग का संकेत देती थी, क्योंकि इस घटना में न केवल बट्टो घायल हुआ था, बल्कि कुछ पैदल सिपाही भी घायल हुए थे।

हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि नियम का पहला भाग 16.38 लागू नहीं होता है क्योंकि वादी बिना किसी वर्दी के घटना स्थल पर गया था और जनता के साथ अपने आधिकारिक संबंधों के संबंध में एक पुलिस अधिकारी द्वारा आपराधिक अपराध के

मिशन का सवाल केवल तभी उठ सकता है जब वह अपराध करता है जब वह वर्दी में हो। यह भी आग्रह किया गया कि इससे पहले कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराध को किया गया कहा जा सके, यह कथित अधिकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक अधिकार होना चाहिए। हम इन झगड़ों में कोई ताकत नहीं देख पा रहे हैं। इस मामले के तथ्यों पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दलाल एक पुलिस अधिकारी के अधिकार का प्रयोग करने का इरादा रखता था और भले ही वह सादे कपड़ों में था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने का इरादा नहीं रखता था।

हमारे विचार में, इस मामले में नियम 16.38 के उप-नियम (1) का उल्लंघन हुआ था। डी.डब्ल्यू. 2, रघु नाथ ने स्वीकार किया कि 22 तारीख को जून 1957 एस के तहत एक मामला। 324 आई.पी.सी. हरिजनों के कहने पर दर्ज किया गया था और यह जाँच ए.आई.सी. होरी लाल और फिर एस.आई. दौलत राम द्वारा की गई थी। उन पर लगे आरोप राम किशन और अन्य ने कहा कि उन्होंने चाकू मारा था श्रीमती बट्टो, एक हरिजन महिला को चोट लगी और चिकित्सा रिपोर्ट से पता चला कि चोट एक कुंद हथियार से लगी थी, हालांकि चोट साधारण थी। उन्होंने आगे कहा कि एस.पी. ने उन्हें एक शुरू करने का आदेश दिया। वादी के खिलाफ विभागीय जांच। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल कोई जानकारी दी गई थी। वादी के खिलाफ प्राप्त शिकायत का विवरण। भी नहीं है। वहाँ कोई सबूत है कि जिला मजिस्ट्रेट ने फैसला किया कि जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिन्होंने इसे किया था।

सरकार के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया। विभागीय प्रक्रिया में दलाल के खिलाफ आरोप के संबंध में एक आपराधिक अपराध के आयोग के साथ जनता के साथ उनके आधिकारिक संबंध। आरोप इस प्रकार हैः

"कि आपको सुबह 8:30 बजे 22-6-57 पर भेजा गया था डी.डी. नंबर 9 दिनांकित 22-6-57 के माध्यम से साइकिल चोरों की जाँच करना पी.एस. फैज़ बाज़ार, लेकिन अपनी ड्यूटी की जगह और साथ छोड़ दिया जिस रास्ते से आपने एफ.सी.एस. लेख राज सं. 6512 और भगत राम नं. 1952 लिया था।

आप तीनों एफ.सी. के साथ थे। उल्लेख किया गया। ऊपर राउस के क्षेत्र में हरिजन बस्ती में गया। कुछ 'सत्तबाज़' की तलाश में एवेन्यू कि।

आप या आपके किसी भी एफ.सी. पुलिस वर्दी में नहीं थे।

कि आपने बैठे हुए कुछ हरिजनों पर छापा मारा बिना अपनी पहचान बताए एक पेड़ के नीचे खाट पर जुआ खेलने के बहाने। वह झगड़ा आपके दो एफ.सी. के बीच हुआ था।

ठाकुर दयाल सं. 6105 और भगत राम सं. 1952 और हरिजन, जहाँ इन दो एफ.सी. में और मोहन लाल की माँ श्रीमती बट्टो घायल हो गईं।

कि कोई स्वतंत्र गवाह या मुखबिर पक्ष में नहीं था। आपके द्वारा जांच अधिकारी के सामने दिखाने के लिए बहकाया गया चाहे आपका छापा प्रामाणिक प्रकृति का था या नहीं।

इसलिए, मैं आप पर कर्तव्य की घोर लापरवाही का आरोप लगाता हूं। लेकिन ए. एल. के सारांश में अंतिम वाक्य के अनुसार इस कार्रवाई पर कर्तव्य की घोर लापरवाही और आचरण करें।

यह हमें लगता है कि यह बचने के लिए एक रंगीन प्रयास था। पुलिस नियम 16.38 उप-नियम (1)। यह आपराधिक का स्पष्ट मामला है। अपराध और यह केवल एक उपकरण था जिसे घोर लापरवाही कहा जा सकता था।

मामले के बाद दिल्ली प्रशासन बनाम चानन शाह[1] [1969] 3 एस.सी.आर. 653) मान लीजिए कि इस मामले में कोई अनुपालन नहीं हुआ है। नियम 16.38, उप-नियम (1) के किसी भी मामले में, बर्खास्तगी का आदेश है। परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज कर दी गई।

वी.पी.एस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।